शिक्षा क्षेत्र में नई क्राँति
गरीब भी अब निजी विद्यालयों में

गरीबों के लिए निजी विद्यालय एवं निवेशकों के लिए नया कार्यक्षेत्र

जेम्स टूली

सारांश

आमतौर पर लोग सोचते हैं कि गरीबों के लिए अनुदान सहायता (डॉनर एड) के रूप में लोक शिक्षा पर अरबों–खरबों डॉलर और अधिक खर्च करने की जरूरत है। लेकिन यह इस सच्चाई को नजरंदाज करता है कि गरीब अभिभावक सरकारी स्कूलों को छोड़ कर अपने बच्चों को बजट प्राइवेट स्कूलों[1] में भेज रहे हैं। ये बजट प्राइवेट स्कूल बहुत कम शुल्क लेते हैं, जो दिहाड़ी पर काम करने वाले अत्यधिक गरीब अभिभावकों द्वारा आसानी से वहन किया जा सकता है।

हालिया रीसर्च में पाया गया कि भारत एवं अफ्रीकी उप–सहारा क्षेत्र के कुछ खास शहरी एवं सीमांत शहरी क्षेत्रों[2] में अधिकांश स्कूली बच्चे निजी स्कूलों में जाते हैं, जबकि ग्रामीण भारत में आधे स्कूली बच्चे निजी स्कूलों में दाखिल हैं। चीन के गरीब गाँवों में भी बड़ी संख्या में निजी विद्यालय चल रहे हैं, जिनकी सरकार को भनक तक नहीं है। शोध से पता चलता है कि गरीबों के लिए चलने वाले निजी विद्यालयों का शिक्षा–स्तर सरकारी स्कूलों से बेहतर है। शिक्षक अधिक समर्पित हैं। महत्त्वपूर्ण अध्ययन सामग्रियों[3] के प्रावधान बेहतर हैं तथा समान पृष्ठभूमि वाले बच्चों में भी निजी विद्यालयों के बच्चों का शिक्षा परिणाम बेहतर है। और इन निजी विद्यालयों में यह सब सरकारी स्कूलों में होने वाले प्रति–छात्र शिक्षक लागत के अंश मात्र में होता है।

विकासकर्मियों के लिए गरीबों की सहायता करने का एक तरीका यह है कि वे लक्षित वाउचर द्वारा निजी स्कूलों में गरीब विद्यार्थियों की पहुँच बढ़ाएँ। फिर भी यह तथ्य कि बजट प्राइवेट स्कूल एक व्यवसाय है, इसमें अच्छा–खासा मुनाफा निकल सकता है, अर्थात् यह अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू निवेशकों को एक नया सृजन क्षेत्र प्रदान करता है, क्योंकि प्रतियोगितापूर्ण बाजार में काम करने वाले शिक्षा उद्यमी स्कूल सुधार हेतु निवेशकों के धन के लिए लालायित हैं। अतः निवेशकों के लिए भी इस प्रक्रिया में भाग लेने की गुंजाइश है और उसके तीन संभावित रास्ते तलाशे गये हैं। माइक्रोफाइनैंस किस्म के ऋण का प्रावधान कर बजट प्राइवेट स्कूलों की मूलभूत संरचना में सुधार लाया जा सकता है। बेहतर पाठ्यक्रम एवं अध्यापन तकनीक में निवेश के ऐसे अवसरों की खोज की जा सकती है, जिसे व्यावसायिक आधार पर चलाया जा सके। अंततः बजट प्राइवेट स्कूलों के ब्रांड में निवेश करने, एक समर्पित शैक्षिक निवेश फंड द्वारा या शिक्षा उद्यमियों के साथ संयुक्त उद्यम द्वारा, से गरीब अभिभावकों की सूचना समस्या के समाधान का रास्ता निकल सकता है, यही नहीं, उनके बच्चों के शिक्षा अवसरों में भी सुधार आ सकता है।

[1] बहुत कम शुल्क लेने वाले गरीबों के निजी विद्यालयों को 'बजट प्राइवेट स्कूल' या 'बजट निजी स्कूल' कहते हैं।

[2] सीमांत शहरी क्षेत्र : शहर के आस–पास बसे छोटे–मोटे गाँव एवं कस्बे या अन्य प्रकार के क्षेत्र।

[3] इनपुट, प्रोसेस एवं आउटपुट। शिक्षा में ये तीन चीजें महत्त्वपूर्ण होती हैं। इसे हिंदी में सामग्री, प्रक्रिया एवं परिणाम कहा जा सकता है। इनपुट या सामग्री के अंतर्गत वे समस्त सहायक उपकरण या व्यवस्था आ जाएंगीं, जिसके सहारे अध्ययन की प्रक्रिया संपन्न होतीं हैं।

विलियम इस्टरली अपनी ताजा तरीन पुस्तक *दी व्हाइट मैन'स बर्डेन* की शुरुआत एवं अंत एक दस वर्षीय ईथियोपियाई लड़की अमारेच, जिसके नाम का अर्थ होता है : ''सुंदरी'', की हृदय विदारक कहानी से करते हैं। ''अदीस अबाब से बाहर यात्रा करते हुए'' वे ''शहर जाने वाली महिलाओं एवं लड़कियों की एक अंतहीन कतार'' से होकर गुजरते हैं (2006, पृ॰ 1)। अमारेच का पूरा दिन सफेदा पेड़ (यूकेलिप्टस) की टहनियाँ चुनने में गुजरता है, ताकि उसे शहर में बेच कर कुछ कमाया जा सके। लेकिन वह स्कूल जाना अधिक पसंद करती, यदि उसके अभिभावक उसे वहाँ भेज पाते। इस्टरली अपनी पुस्तक ''उसे और उस जैसे करोड़ों बच्चों को समर्पित करते हैं''। पुस्तक की आखिरी पंक्ति (पृ॰ 384) में वे पुनः अमारेच पर पहुँचते हुए कहते हैं : क्या आप खोजियों में से कोई इस लकड़चुन्नी ईथियोपियाई बाला, अमारेच, को स्कूल भेजने का कोई रास्ता निकाल सकते हैं?

विकासशील देशों में ऐसे अनेक ''खोजी'' –हर तरह के उद्यमियों के लिए इस्टरली द्वारा दिया गया शब्द– हैं, जो अमारेच जैसी परिस्थिति में रह रहे बच्चों के लिए रास्ता बनाने में पहले से ही लगे हैं। स्वीकृत धारणा यह है कि इससे पहले कि अमारेच जैसे बच्चे शिक्षा पाएं, लोक शिक्षा व्यवस्था में अरबों डॉलर के अनुदान की जरूरत पड़ेगी और गरीबों को ''लंबा इंतजार'' (विश्व बैंक 2003, पृ॰ 1) करना पड़ेगा, क्योंकि गरीबों को कोई शिक्षा मिल पाने से पहले लोक शिक्षा व्यवस्था में सुधार कर उसे भ्रष्टाचार तथा घोर अकर्मण्यता से मुक्ति दिलानी होगी।

ऐसा लगता है कि स्वीकृत धारणा दिग्भ्रमित है। यह इस सच्चाई पर गौर नहीं करती कि बड़ी संख्या में अभिभावकों ने पहले ही लोक शिक्षा व्यवस्था को त्याग दिया है–इसकी पस्तहालत एवं गैरजिम्मदारी के कारण–और इसकी जगह निजी स्कूलों को वरीयता देने लगे हैं। निवेशक समुदाय के लिए यह तथ्य बड़े महत्त्व का है एवं इसके गहरे अर्थ हैं।

गरीबों के लिए निजी विद्यालयों की क्रांति

हालिया रीसर्च में चीन, घाना, भारत, केन्या और नाइजीरिया के कुछ चुने हुए सरकारी तौर पर मान्य गरीब क्षेत्रों में गरीबों की शिक्षा के संदर्भ में खोजबीन की गयी।[4] शोधार्थी दल ने इन देशों के महानगरों की अनियमित बस्तियों–झुग्गी झोपड़ियों–तथा इन नगरों के आस–पास के गाँवों के गरीब क्षेत्रों की खाक छानी। उन्होंने चीन के गरीब उत्तरपश्चिमी क्षेत्र के सुदूर देहातों तथा दक्षिण भारत के ग्रामीण इलाकों में शोध किये। शोधार्थी दल ने इन क्षेत्रों का चप्पा–चप्पा छान मारा, झुग्गियों की हर एक गली–कूची में गये, गाँव के हर टोले–महल्ले में गये, चौक–चौराहों पर आम लोगों से बातें कीं और पता लगाया कि गरीबों के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं।

उन्हें बड़ी संख्या में स्कूल मिले–उदाहरण के तौर पर 918 स्कूल हैदराबाद, भारत के तीन जोनों की अधिसूचित झुग्गी बस्तियों में मिले। उन्हें जहाँ भी स्कूल मिले, चाहे वे सरकारी हों या निजी, उन्होंने स्कूल प्रबंधकों से बात की तथा बगैर बताए स्कूल की प्राथमिक कक्षाओं में जाकर शिक्षकों की गतिविधियों का मूल्यांकन किया तथा कुछ पूर्व निर्धारित स्कूल सामग्रियों (स्कूल इनपुट्स) के बारे में पता किये। शोधार्थियों ने इन गरीब बस्तियों के वर्गीकृत रैंडम नमूना स्कूलों[5] से लगभग 24,000 बच्चों की परीक्षा ली। पृष्ठभूमि संबंधी ढेरों मुद्दों, साथ ही सहपाठी समूह के भी विभिन्न मुद्दों के संदर्भ में आँकड़े जुटाने हेतु प्रमुख पाठ्यक्रम विषयों में बच्चों की जाँच की गयी एवं बच्चों, उनके अभिभावकों, शिक्षकों तथा स्कूल प्रबंधकों को प्रश्नावलियाँ दी गयीं और बच्चों तथा उनके शिक्षकों की आइ क्यू जाँच की गयी।

शोधार्थी दल को प्राप्त तथ्य शिक्षा में हो रही क्रांति की ओर इशारा करते हैं। सर्वेक्षण किये गये शहरी गरीब एवं सीमांत शहरी इलाकों में स्कूली बच्चे बड़ी तादाद में ''बजट'' निजी स्कूलों में पढ़ते पाये गये। उदाहरण के तौर पर नाइजीरिया के लागोस राज्य के गरीब शहरी तथा सीमांत शहरी इलाकों के 75 फीसदी स्कूली बच्चे निजी विद्यालयों में पढ़ रहे थे। घाना के गा स्थित सीमांत शहरी जिले में यह आँकड़ा 64 फीसदी था, जबकि भारत के हैदराबाद की

[4] लेखक द्वारा किये गये शोध का खर्च जॉन टेंपल्टन फाउंडेशन ने वहन किया है।

[5] वर्गीकृत रैंडम नमूना स्कूल : विभिन्न श्रेणी या वर्ग में स्कूलों का रैंडम नमूना अर्थात अलग–अलग श्रेणियों में बिना किसी पूर्वाग्रह के स्कूलों का चयन।

झुग्गियों में 65 फीसदी स्कूली बच्चे गैरसहायता प्राप्त निजी स्कूलों (प्राइवेट, अनएडेड स्कूल) में पढ़ रहे थे (तालिका 1)।

ये बजट निजी स्कूल आमतौर पर इन गरीब इलाके के उद्यमियों द्वारा ही स्थापित किये जाते हैं, जिसमें शिक्षकों की भर्ती भी इन्हीं समुदायों से होती है, सरकारी विद्यालयों की भांति नहीं, जहाँ शिक्षक आमतौर पर बाहर से आते हैं। इन निजी विद्यालयों का शुल्क बहुत कम होता है, जिसे देने में गरीब अभिभावकों, जो गरीबी रेखा एवं न्यूनतम मजदूरी पर गुजर बसर कर रहे हैं, को कोई दिक्कत नहीं होती। उदाहरण के तौर पर, हैदराबाद की झुग्गियों में, चौथी कक्षा का औसत मासिक शुल्क गैरमान्यताप्राप्त निजी विद्यालयों में 78.17 रुपये (1.74 $) तथा मान्यताप्राप्त निजी विद्यालयों में 102.55 रुपये (2.28 $) थे। ये शुल्क एक मजदूर की मासिक आय का क्रमशः लगभग 4.2 फीसदी तथा 5.5 फीसदी बैठता है, जो औसतन लगभग 78 रुपये प्रतिदिन की न्यूनतम मजदूरी कमाते हैं (महीने में 24 कार्यदिवसों के हिसाब से; भारत, लेबर ब्यूरो 2005)।

गरीबों के लिए निजी विद्यालय का चलना कोई शहर या सीमांत शहर की ही बात नहीं है। ग्रामीण आंध्रप्रदेश, भारत के एक गरीब जिला महबूबनगर में मोटे तौर पर आधे स्कूली बच्चे गैरसहायताप्राप्त निजी विद्यालयों में पढ़ते थे (देखें तालिका 1)। ग्रामीण गांसू, चीन के दूर–दराज गाँवों में सरकारी आँकड़ों के अनुसार एक भी निजी विद्यालय नहीं चल रहे हैं, परंतु शोध में 586 निजी विद्यालय पाये गये, जो 59,958 बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। (अधिक जानकारी के लिए कृपया देखें : टूली, 2005; टूली एवं डिक्सन, 2005, 2006a, 2006b; तथा टूली, डिक्सन एवं ओलेनियन, 2005; टूली, डिक्सन एवं गोमथि, 2007; टूली, डिक्सन एवं अमुआ, 2007)।

वस्तुतः इस विस्तृत शोध को सप्लीमेंट करने के लिए जहाँ भी अध्ययन देखे गये, गरीबों के लिए ऐसे ही निजी विद्यालय पाये गये–सोमालीलैंड में युद्ध में क्षतिग्रस्त भवनों में, जिंबाबवे के जल्द ही उजाड़ दिये जाने वाले पिछड़े इलाकों में, तथा सिएरा लियोन के फ्रीटाउन की निर्धन झुग्गियों में। और मालावी, तंजानिया, तथा युगांडा में; भारत के अन्य राज्यों में; पाकिस्तान में; कैरीबियन में तथा अन्य जगहों पर भी गरीबों के लिए चल रहे निजी विद्यालय देखने को मिले। ऐसा प्रतीत होता है कि गरीबों के लिए निजी विद्यालयों का उभार विकासशील विश्व में हर जगह हो रहा है। (कृपया देखें, उदाहरण के तौर पर, साल्मी 2000; रोज 2002; वाटकिंस 2000; अग्रवाल 2000; डी एवं अन्य 2002; एवं एल्डरमैन, किम, तथा ओराजेम 2003)।

यद्यपि कई डेवलपमेंट विशेषज्ञ जो हर जगह समान रूप से इन विद्यालयों की उपस्थिति से अवगत हैं, इनकी गुणवत्ता को निम्नस्तरीय बताते हुए चिंता व्यक्त करते हैं। उदाहरण के तौर पर *ऑक्सफेम एडूकेशन रिपोर्ट* में कहा गया है कि गरीबों के निजी विद्यालय ''निम्न स्तर'' के हैं तथा ''घटिया सेवा'' प्रदान करते हैं। यह ''बच्चों को भविष्य में अवसरों से वंचित कर देंगे'' (वाटकिंस 2000, पृ॰ 230)। नाइजीरिया में गरीबों के निजी विद्यालयों को लोक शिक्षा का ''सस्ता तथा निम्नस्तरीय विकल्प'' प्रस्तुत करते हुए दर्ज किया गया (एडलाबु एवं रोज, पृ॰ 74)।

ताजा शोध से प्राप्त तथ्य इस बात को रेखांकित करते हैं कि ऐसी चिंताएँ निराधार हैं – कम–से–कम लोक शिक्षा की गुणवत्ता की तुलना में। प्रत्येक समुच्च्य में, सरकारी विद्यालयों की तुलना में गरीबों के निजी विद्यालयों में शिक्षकों की अनुपस्थिति कम तथा शिक्षकों की प्रतिबद्धता – वास्तव में पढ़ा रहे शिक्षकों का अनुपात, जब हमारे शोधार्थियों ने बगैर पूर्व सूचना के संपर्क किया – अधिक थी। सिर्फ एक बिन्दु – खेल के मैदान का प्रावधान – पर सरकारी विद्यालय समूचे अध्ययन क्रम में निजी विद्यालयों से ऊपर ठहरे। बाकी सभी बिंदुओं – जैसे, पेयजल, शौचालय, मेज, कुर्सी, पुस्तकालय, विद्युत पंखे एवं प्रकाश व्यवस्था तथा शिक्षण के लिए टेप रेकॉर्डर – पर गरीबों के निजी विद्यालय सरकारी विद्यालयों से ऊपर थे।

खास तौर पर, हर जगह निजी विद्यालयों ने परफॉरमेंस के मामले में सरकारी विद्यालयों को पाठ्यक्रम के प्रमुख विषयों में पीछे छोड़ा–पृष्ठभूमि संबंधी विभिन्न मुद्दों को स्थिर करने के बाद भी[6]। लागोस राज्य में, उदाहरण के तौर पर, गणित विषय की परीक्षा में विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक सरकारी विद्यालय की तुलना में निजी पंजीकृत एवं गैरपंजीकृत विद्यालयों में क्रमशः 14 एवं 19 प्रतिशत ज्यादा था, जबकि अंग्रेजी विषय में यह 22 एवं 29 प्रतिशत ज्यादा था। और पृष्ठभूमि संबंधी कारकों को स्थिर करने के बाद, तथा, इस बात को मानते हुए कि विद्यार्थी विभिन्न स्कूल प्रबंधन किस्मों में सोच–विचार कर ही दाखिल किये गये थे, हमने पाया कि यह अंतर यद्यपि कम हुआ, फिर भी स्कूल चयन प्रक्रिया का झुकाव काफी हद तक निजी शिक्षा के ही पक्ष में था। लागोस राज्य, नाइजीरिया में, एक औसत सैंपल बच्चे का पूर्वानुमानित गणित प्राप्तांक सरकारी विद्यालय में 45.1 प्रतिशत था, गैरपंजीकृत विद्यालय में उसी औसत बच्चे के लिए 53.5 प्रतिशत था, एवं पंजीकृत निजी विद्यालय में 57.6 प्रतिशत था। अंग्रेजी के लिए भी एक औसत सैंपल बच्चे का पूर्वानुमानित प्राप्तांक सरकारी विद्यालय में 45.1 था, जबकि दोनों ही प्रकार के निजी विद्यालयों की उपलब्धियों में कोई खास अंतर नहीं था – इन विद्यालयों में उसी बच्चे के लिए पूर्वानुमानित प्राप्तांक 64.4 प्रतिशत था।

गौर करने वाली बात यह है कि सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों पर जितना खर्च होता है, उसकी अपेक्षा बहुत कम खर्च में ही निजी विद्यालय सरकारी विद्यालयों को मात दे रहे थे, जबकि शिक्षक–खर्च विद्यालय के नियमित–खर्चे का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। यही नहीं प्रति–विद्यार्थी शिक्षक–खर्च का हिसाब लगाने पर भी (यहाँ यह भी ध्यान रखें कि कक्षा का आकार, यानी, एक कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या, हमेशा सरकारी विद्यालयों में ही सबसे ज्यादा बड़ा था) निजी विद्यालय कम खर्चीला साबित हुआ। लागोस राज्य में, उदाहरण के तौर पर, प्रति–विद्यार्थी शिक्षक–खर्च सरकारी विद्यालयों में निजी विद्यालयों की अपेक्षा ढाई गुणा ज्यादा था।

तेजी से बढ़ते हुए एवं उर्जावान निजी क्षेत्र की उपस्थिति एक रास्ता दिखाती है, जिसमें इस्टरली की अमारेच को पहुँचाया जा सकता है–लक्षित वाउचर एवं छात्रवृत्ति के माध्यम से अमारेच जैसे उन सभी बच्चों को, जिनके माँ–बाप निजी विद्यालयों का खर्च उठा पाने में असमर्थ हैं। (निजी शिक्षा लेने के लिए गरीबों अभिभावकों के ही हाथ में फंड दे देकर शिक्षा उद्यमियों को वहाँ भी स्कूल स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है, जहाँ आज समुचित व्यवस्था नहीं हैं।) वस्तुतः निजी विद्यालयों के मालिक खुद इसके लिए रास्ता दिखा रहे हैं–अनाथों तथा विधवा माता की संतानों जैसे निर्धनों में भी निर्धनतम विद्यार्थियों के लिए उनके यहाँ निःशुल्क अथवा सब्सिडाइज्ड खर्च पर दाखिला दिया जाता है। हैदराबाद की झुग्गियों में, उदाहरण के तौर पर, शोध में पता चला कि निजी विद्यालयों में कुल स्थान का 18 प्रतिशत मुफ्त अथवा छूट के साथ दाखिला दिया जाता है। इस मानवीय व्यवस्था को अगर विकसित होने का मौका दिया जाए, तो वहाँ अमारेच को दाखिला मिल जाएगा। इन स्कूलों में शिक्षक अधिक जिम्मेदार होंगे, सरकारी विद्यालयों की भांति नहीं, जिस पर विकास एजेंसियाँ आरोप लगाया करती हैं कि शिक्षक हमेशा कक्षा से नदारद रहते हैं तथा उनमें प्रतिबद्धता की भी घोर कमी है।

निवेश के अवसर के रूप में शिक्षा उद्यम

अमारेच को विद्यालय में जगह दिलवाने की चुनौती का समाधान है। पर उस विद्यालय की गुणवत्ता का क्या भरोसा, जिसमें उसका दाखिला होगा? यहीं पर निवेशकों की एक नयी सृजनात्मक भूमिका सामने आती है। एक ऐसी भूमिका, जिसमें निवेशक लोग गरीबों के जीवन में व्यापक बदलाव लाने की क्षमता रखते हैं। शोध से एक बड़ी महत्त्वपूर्ण तथा प्रासंगिक बात का खुलासा होता है कि गरीब क्षेत्रों में चलने वाले निजी विद्यालयों में अधिकांश विशुद्ध व्यवसाय के रूप में चलते हैं, न कि समाज सेवा के रूप में। ये निजी विद्यालय कमोबेश शुल्क से होने वाली आय पर चलते हैं तथा सबसे महत्त्वपूर्ण यह कि वे समुचित मुनाफा भी कमा रहे हैं। गा, घाना में, उदाहरण के तौर पर 82 फीसदी पंजीकृत एवं 93 फीसदी गैरपंजीकृत निजी विद्यालय उनके मालिकों की निजी मिल्कियत थी। हैदराबाद में 91 फीसदी

[6] परफॉरमेंस विश्लेषण करते समय विद्यालयों के पृष्ठभूमि संबंधी मुद्दों को भी ध्यान में रखा गया। उदाहरण के तौर पर सरकारी विद्यालय के गरीब विद्यार्थियों के समूह की तुलना में निजी विद्यालयों के भी उसी पृष्ठभूमि के बच्चों को रख कर विश्लेषण किया गया। इसी प्रकार पृष्ठभूमि संबंधी अन्य मुद्दों को स्थिर करने के बाद भी निजी विद्यालयों की उपलब्धि बेहतर साबित हुई।

गैरमान्यताप्राप्त तथा 82 फीसदी मान्यताप्राप्त निजी विद्यालय पूरी तरह से विद्यार्थियों के शुल्क पर ही आश्रित थे तथा बाहरी स्रोत से कोई फंड नहीं लेते थे।

वित्तीय स्थिति की बेहतर जानकारी के लिए शोध में हर सेटिंग में 10–15 केस स्टडी स्कूलों के जरिए स्कूल को होने वाले मुनाफे का पता लगाया गया। प्रत्येक मामले में इन विद्यालयों के औसत से उसके मालिक को होने वाले अच्छे–खासे लाभ का पता चलता है। उदाहरण के तौर पर, लागोस राज्य के मकोको के एक पिछड़े इलाके में एक आदर्श केस स्टडी स्कूल में 220 छात्र थे, 13 शिक्षक थे एवं औसत शुल्क प्रति टर्म N 1,800 ($12.41) था तथा 9 फीसदी विद्यार्थी पूर्णतः छात्रवृत्ति पर थे। शिक्षकों का औसत वेतन प्रति माह N 4,388 ($30.26) था, अन्य नियमित खर्च था प्रतिमाह N 7,450 ($51.38) एवं प्रोपराइटर का मासिक वेतन था N 8,000 ($55.17)। इस प्रकार के एक विद्यालय का सलाना सरप्लस था लगभग $1,456 या उनकी आय का लगभग 20 फीसदी (तालिका 2)।

चूँकि गरीबों के लिए चलने वाला निजी विद्यालय एक व्यवसाय होता है, यह निवेशकों को गुणवत्ता सुधार में मदद करने हेतु कम–से–कम तीन रास्ते उपलब्ध कराता है। पहला रास्ता है स्कूल प्रोपराइटर को स्कूल की आधारभूत संरचना में सुधार के लिए माइक्रोफाइनैंस ऋण के माध्यम से मदद उपलब्ध कराना। यह काम पहले से चल रहे अथवा इस विशेष उद्देश्य हेतु स्थापित माइक्रोफाइनैंस संस्थान के जरिए हो सकता है। हैदराबाद एवं लागोस में शोध के दौरान दो पायलट ऋण योजना चलायी गयी थी। इस योजना के तहत 500–2,000 $ का ऋण व्यावसायिक ब्याज दर पर निजी विद्यालय के प्रबंधकों को अपनी आधारभूत संरचना में विकास के लिए दिया गया था। परियोजना में आमतौर पर शौचालयों का निर्माण, नयी कक्षाओं का निर्माण अथवा नवीनीकरण एवं जमीन खरीदना शामिल होता था।

पायलट ऋण योजना से उन निजी विद्यालयों के अंदर वित्तीय स्रोत की जबरदस्त भूख का पता चलता है, जो आमतौर पर अन्य फंड हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास संपत्ति का औपचारिक अधिकार नहीं होता है अथवा वे पूर्णतः वैध नहीं होते हैं–हरनांडो डि सोटो ने *मिस्टरी ऑफ कैपिटल* (2000) में इस प्रकार के व्यवसायों को प्रमुखता से रखा है। ये पायलट निजी विद्यालयों के मालिकों को ऋण देने हेतु बड़े स्तर की माइक्रोफाइनैंस परियोजना में निवेश की संभाव्यता की ओर इशारा करते हैं। वित्तीय सलाह जैसी तकनीकी सहायता इन निवेशों में पूरक की भूमिका निभा सकती है। निजी विद्यालय की आधारभूत संरचना में सुधार की समस्या का इस प्रकार सरलता से समाधान किया जा सकता है।

लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता का क्या? गरीबों के निजी विद्यालयों में सामान्यतः तोता रटंत[7] शिक्षण पद्धति एवं राजकीय पाठ्यक्रम अपनाए जाते हैं। इस तोतारटंत पद्धति का रूप विकासशील देशों में हर जगह पारंपरिक है तथा राजकीय पाठ्यक्रम एक तो, ऐसे–ऐसे विषयों से लदे होते हैं, जिनमें से अधिकतर की शायद ही गरीब बच्चों के लिए कोई प्रासंगिकता हो, दूसरे, उनमें बच्चों के महत्त्व के विषय भी नदारद होते हैं, जैसे उद्यम शिक्षा। विकासकर्मी इन मुद्दों को लेकर भी काफी गंभीर हैं, जैसे – वर्तमान अध्यापन पद्धति ''काफी कठोर'' है, ''रट्टू शिक्षण शैली पर भरोसा, जिसमें विद्यार्थियों को निष्क्रिय भूमिका में'' रखा गया है (यूनेस्को, 2004, पृ. 17, देखें डेंबेल एंड मियारो–II 2003)। पाठ्यक्रमों में ''बच्चों के सामाजिक–सांस्कृतिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता की कमी'' है (यूनेस्को 2004, पृ. 31)।

शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए विकास एजेंसी आमतौर पर जो तरीका अपनाती है, उसके तहत शिक्षकों की अध्यापन शैली बदलने तथा विद्यार्थियों को निष्क्रिय अध्ययन शैली से बाहर निकालने पर करोड़ों रुपये खर्च किये जाते हैं। हाइटेक समाधानों–टेलीविजन, इंटेरेक्टिव रेडियो या सूचना प्रौद्योगिकी–पर बहुत खर्च किये गये, शिक्षकों को पूर्णतः नजरंदाज करने हेतु, शिक्षकों को नयी तकनीकों का प्रशिक्षण देने हेतु या शिक्षण को इन आधुनिक पद्धतियों से संपूर्ण करने हेतु (देखें, उदाहरण के तौर पर, लीच 2005; रोड्स एवं रॉस्मुसेन–टॉल 2005; ईडीसी 2001; मर्फी एवं अन्य 2002; एवं पॉटर एवं सिल्वा 2002)।

[7] तोता रटंत : अध्यापन की एक पिछड़ी शैली, जिसमें विद्यार्थियों को पाठ रटा दिया जाता है, समझाया नहीं जाता।

लेकिन इन खर्चीले प्रयासों का कोई खास प्रभाव पड़ता नहीं दिखाई पड़ता है। जैसे ही सहायता मिशनों का काम खत्म होता है, शिक्षक प्रायः पुनः अपने पुराने सुविधाजनक ढर्रे पर लौट आते हैं (देखें, उदाहरणस्वरूप, मर्फी एवं अन्य 2002)। ऐसी परियोजनाएँ गरीबों में इन प्रयासों को जारी रखने अथवा इनमें खर्च करने हेतु किसी प्रकार के प्रोत्साहन का विकास नहीं कर पाती हैं। जबकि तेजी से उभर रहे निजी विद्यालयों के बाजार की उपस्थिति ऐसे निवेश अवसरों के मार्ग प्रस्तुत करती है, जो वास्तव में शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिए प्रोत्साहन का विकास करता है। निजी शिक्षा के कड़ी प्रतियोगिता वाले बाजारों में ऐसे प्रोत्साहन, जिसके पीछे कोई पारंपरिक अनुदान नहीं होता, सर्वव्यापक एवं सर्वोपरि हैं।

ये प्रोत्साहन या प्रेरक–तत्त्व हाल ही हैदराबाद की झुग्गी बस्तियों के एक निजी विद्यालय में डॉ॰ सुगाता मित्रा के सहयोग से की गयी एक लघ्वाकार (स्मॉल स्केल) परियोजना में साफ तौर पर उजागर हुए। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियों में से एक नीट लि. (NIIT Ltd.) में शोध निदेशक मित्रा ने सूचना प्रौद्योगिकी के सहारे सहपाठी समूह शिक्षा (पीयर ग्रुप लर्निंग, जिसमें विद्यार्थी दोस्तों के साथ बातों–बातों में प्रयोग करते हुए जिज्ञासावश कुछ सीखते हैं) पर प्रयोग किया, जिसे मीडिया द्वारा ''द होल इन द वाल (दीवाल में छिद्र)[8]'' नाम से प्रसारित किया गया (देखें मित्रा 2005)। हैदराबाद में कॉल सेंटरों की बाढ़ आयी हुई है। इन 'गरीबों के निजी विद्यालयों' से निकले बहुत–से विद्यार्थी इनमें नौकरी पाने की कोशिश करते हैं, पर अपने अंग्रेजी उच्चारण दोष के कारण पिछड़ जाते हैं। उनके शिक्षक कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वे भी अंग्रेजी बोलने में कुशल नहीं होते हैं। परियोजना ने ''होल इन द वाल'' नजरिए से कोशिश की : क्या बच्चे खुद अपनी कोशिशों के बल पर अपने अंग्रेजी उच्चारण सुधार सकते हैं?

स्पीच–टू–टेक्स्ट (बोली से लिपि में रूपांतर) कार्यक्रम के विवरणों (देखें मित्रा एवं अन्य 2003) में यहाँ जाने की जरूरत नहीं। प्रयोग से पता चलता है कि यह पद्धति अंग्रेजी उच्चारण सुधारने में काफी कारगर रही। लेकिन प्रयोग समाप्त होने के बाद जो हुआ, वह यहाँ सबसे ज्यादा प्रासंगिक है। बहुत–से दूसरे निजी विद्यालयों के मालिक, जिन्होंने इस प्रयोग के बारे में सुना, वे इस तकनीक को अपने विद्यालयों में भी चाहते थे और इसके लिए खर्च करने को भी तैयार थे। पहले निवेश का तरीका था, उपयुक्त मुनाफा निकल जाने के बाद, सैकेंड हैंड कंप्यूटर खरीदना एवं एक शिक्षक रखना। अब वे ही मालिक कहने लगे : शायद हमें कंप्यूटर शिक्षक की जरूरत नहीं। हमें ''होल–इन–द–वाल'' की जरूरत है।

स्कूल मालिक नये प्रयोगों के लिए बेकरार थे। क्यों? बहुत सीधा कारण है। *गरीबों के निजी विद्यालयों* के आलोचक चाहे कुछ भी आरोप मढ़ते रहें, पर सच्चाई यह है कि अधिकतर विद्यालय बच्चों की शिक्षा को लेकर काफी गंभीर रहते हैं। बस इतना ही काफी है किसी के लिए नयी तकनीक में निवेश करने हेतु। लेकिन बाजार की ताकत का मतलब यह होता है कि इसमें अन्य प्रोत्साहन एवं उत्प्रेरक भी जुड़ जाते हैं : मालिक जानते हैं कि वे एक अत्यधिक प्रतियोगी बाजार में हैं। अपना बाजार शेयर स्थिर रखने अथवा बढ़ाते रहने के लिए स्कूल मालिकों के लिए अभिभावकों को यह बतलाते रहना जरूरी है कि उनका स्कूल अन्य स्कूलों की अपेक्षा कुछ खास है। अगर कहीं अध्ययन–अध्यापन की किसी तकनीक का बेहतर परिणाम आ रहा होता है, तो वे उसे अपने विद्यालय में भी लाना चाहते हैं।

यह निवेशकों को टिकाऊ शैक्षिक सुधार में सहायता करने का एक दूसरा रास्ता दिखाता है। निवेशक – अगर जरूरी हुआ तो प्रारंभिक खतरों के मद्देनजर डॉनर फंड के बल पर – एक लघु आकार का रीसर्च एवं डेवलपमेंट (आर एंड डी) कर सकते हैं, जिस प्रकार का प्रयोग हैदराबाद में मित्रा के सहयोग से किया गया, यह जानने के लिए कि इच्छित पाठ्यक्रम एवं अध्यापन परिणाम में सुधार के लिए कारगर समाधान क्या हो सकता है। तत्पश्चात् निवेशक स्थानीय उद्यमियों से हाथ मिलाकर यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि विकसित तकनीक को उपलब्ध कराया जाए, सही पैकेजिंग के साथ और स्कूल उद्यमियों को स्वीकार्य कीमत पर। किसी भी सहायता कार्यक्रमों (एड इंटरवेंशंस) के

[8] द होल इन द वाल : इस प्रयोग के तहत एक कमरे में कंप्यूटर लगाए गये। और कमरे में प्रवेश करने हेतु एक ओर से दीवार में छिद्र बना दिया गया। ताकि बच्चे खेल–खेल में उसमें प्रवेश करें एवं खुद प्रयोग कर सीखें।

लिए हमेशा सबसे बड़ी चुनौती साबित होने वाली स्थायित्त्व एवं व्यापकता (सस्टेनेबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी) की समस्या इस प्रकार हल हो जाती है।

मित्रा की ''होल–इन–द–वाल'' शिक्षण पद्धति, उदाहरण के तौर पर, आसानी से निजी विद्यालयों में अपनायी जा सकती है। इस प्रौद्योगिकी का खर्च प्रति कियोस्क, तीन कंप्यूटरों के साथ–जो 200 बच्चों को सेवा देता हो–लगभग 2,500 डॉलर आता है। मकोको, नाइजीरिया के पिछड़े–अविकसित इलाके का एक आम–साधारण स्कूल, उदाहरण के तौर पर, आसानी से इस प्रौद्योगिकी को खरीद सकता है, दो–तीन साल के मुनाफे के साथ – या फिर शायद इसके लिए ऋण का भी उपयोग किया जा सकता है (देखें तालिका 2)। सर्वेक्षण किये गये अन्य देशों में तो यह और भी सस्ता पड़ सकता है। इन नवीन प्रयोगों को एक वाजिब कीमत पर उपलब्ध कराने हेतु आधारभूत संरचना स्थापित करने में अंतर्राष्ट्रीय वित्त समुदाय स्थानीय उद्यमियों को सहयोग कर सकते हैं – पुनः, तकनीकी सहायता देकर, अगर जरूरी हो।

ब्रांड के प्रति जागरूक गरीब

द फॉर्च्यून एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड में सी. के. प्रह्लाद इस ''स्थापित सोच'' को चुनौती देते हैं कि ''गरीब ब्रांड नाम की परवाह नहीं करते'' (2005, पृ॰ 13)। ''इसके विपरीत'' उनके विश्लेषण बताते हैं कि ''गरीब लोग ब्रांड के प्रति बहुत सतर्क होते हैं''। शिक्षा व्यवस्था में सूचना का अभाव एक वास्तविक समस्या है और निजी शिक्षा में इस समस्या का समाधान करने की दिशा में ब्रांड नाम बहुत कारगर साबित हो सकता है। और यही वह जगह है, जो निवेशकों को शिक्षा के बाजार में प्रवेश करने का तीसरा बड़ा अवसर प्रदान करता है।

गरीब अभिभावक यह कैसे निर्णय कर सकते हैं कि उनके गाँव–समाज में चलने वाले निजी विद्यालयों में से कौन श्रेष्ठ है, या फिर यह कि उनके बच्चों की शिक्षा जरूरत को कौन विद्यालय अच्छी तरह पूरा कर सकता है? शोध से पता चलता है कि अभिभावक इसके लिए विविध तरीके अपनाते हैं, जैसे– विभिन्न विद्यालय जाकर पता लगाना कि उनके शिक्षक एवं प्रबंधक विद्यार्थियों की शिक्षा के प्रति कितने गंभीर हैं। या फिर वे अपने मित्रों से बात करते हैं, विभिन्न विद्यालयों की पुस्तिकाओं को मिलाकर देखते हैं कि किस विद्यालय में कापियों की कितनी बार जाँच की गयी है एवं गृहकार्य कितनी बारीकी से देखे गये है। गौरतलब है कि अगर अभिभावक ने किसी एक विद्यालय का चयन कर लिया है और उन्हें बाद में पता चलता है कि कोई अन्य विद्यालय बेहतर साबित हो रहा है, तो उन्हें अपने बच्चे को पुरानी जगह से निकाल कर नयी जगह पर दाखिला कराने में ज्यादा संकोच नहीं होता है। और स्कूल मालिक यह सब जानता है, इसलिए यह ध्यान रखता है कि उनके शिक्षक रोजाना आएँ एवं बच्चों को मुस्तैदी से पढ़ाएँ, साथ ही वह मुनाफे को भी पुनः स्कूल की बेहतरी में लगाता है, ताकि उनके अभिभावक विद्यालय से संतुष्ट रहें। इसलिए सूचना की समस्या तो है, पर उनके समाधान के उपाय भी हैं।

यद्यपि, अन्य बाजारों में, ब्रांड नाम समानांतर सूचना अनियमितताओं से निपटने का एक अधिक सुरक्षित रास्ता प्रदान करता है। गरीब अभिभावकों, जो अपने बच्चों के लिए सर्वोत्तम शिक्षा चाहते हैं, के लिए विश्वसनीय ब्रांड की सेवा लेना भी सूचना की समस्या से निपटने का एक तरीका हो सकता है। यह साफ तौर पर देखा जा रहा है कि छोटे–छोटे ब्रांड शिक्षा के बाजार में रोजाना उभरते जा रहे हैं – शिक्षा उद्यमी या तो अपने स्कूल व्यवसाय को फैला रहे हैं, या दूसरे को हस्तगत कर रहे हैं, क्योंकि वे वो चीज दे रहे हैं, जो अधिक अभिभावकों द्वारा पसंद की जाती है। कुछ प्रोपराइटर्स के पास तो चार–पाँच विद्यालय पहले से हैं तथा वे इस संख्या को जल्द ही और भी बढ़ा लेना चाहते हैं।

शैक्षणिक ब्राण्ड नाम के निर्माण में, जो अभिभावकों को पहले से अधिक सूचना के आलोक में फैसले लेने में मदद करेगा, बाजार को मदद करना निवेश के लिए तीसरा संभावित क्षेत्र है। यहाँ पुनः यह ध्यान रखना होगा कि शुरू में

यह डॉनर सपोर्ट के बल पर होगा, अगर ऐसा करना निवेशकों को बाजार की व्यावहारिकता का भरोसा दिलाने के लिए जरूरी होगा। शिक्षा उद्यमियों को वैधानिक एवं वित्तीय मुद्दों पर तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के लिए भी निवेश को डॉनर सपोर्ट के साथ जोड़ा जा सकता है। निवेशकों के लिए एक संभावना यह है कि वे विस्तारवादी सोच रखने वाले स्कूल मालिकों को ऋण संपत्ति का आँकलन करने में सहयोग करें, उसी प्रकार जिस प्रकार यहाँ पहले सुझाया गया है। अथवा वे इसमें ढेर सारे बजट प्राइवेट स्कूल्स चलाने वाले अच्छी तरह एवं वैधानिक रूप से स्थापित शैक्षिक कंपनियों को इक्विटी उपलब्ध कराने के लिए विशिष्ट शिक्षा निवेश फंड का निर्माण भी शामिल कर सकते हैं। निवेश फंड के लिए यथोचित बहिर्गमन नीति तैयार की जा सकती है, शायद यह सलाह देकर कि किस प्रकार स्थानीय स्टॉक मार्केट की सूची में आएँ या अन्य निवेशकों को अपने यहाँ निवेश करने के लिए आमंत्रित करें।

एक अगली संभावना यह हो सकती है कि निवेशकगण स्वयं एक शृंखला स्थापित करने के लिए स्थानीय शिक्षा उद्यमियों के साथ साझा उद्यम में प्रवृत्त हों। गरीबों के लिए शिक्षा का सुस्पष्ट एवं वास्तव में विकल्प बनने की क्षमता रखने वाले मॉडल के लिए मानक तय करने हेतु प्रारंभिक शोध एवं विकास (आर एंड डी, रीसर्च एंड डेवलपमेंट) में निवेश की जरूरत होगी। यह एक वर्तमान स्कूल में ही सबसे अच्छी तरह पूरा किया जा सकता है, जो तब अभिभावकों, निवेशकों तथा संभावित फ्रैंचाइजों को मॉडल की उपयोगिता सिद्ध करेगा – अगर एक फ्रैंचाइज मॉडल को सटीक माना जाएगा – तथा नये स्कूल प्रबंधकों एवं शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रयोग किया जाएगा।

इस प्रकार का आर एंड डी सफल शैक्षणिक मॉडल के लिए तकनीक, पाठ्यक्रम, अध्यापन विधि एवं शिक्षकों के प्रशिक्षण की जरूरत की तथा ब्रांड–नाम शृंखला के लिए गुणवत्ता नियंत्रण, वित्तीय एवं रेगुलेटरी जरूरतों की पड़ताल करेगा। निवेशकों के लिए, गरीब समुदायों को सेवा देने वाले बजट प्राइवेट स्कूलों की शृंखला स्थापित करना एक अत्यधिक उत्साहवर्धक एवं अनूठी परियोजना प्रतीत होती है।

निजी स्कूलों के मालिक फ्रैंचाइज धारक या प्रबंधक के रूप में किसी विद्यालय–शृंखला में क्यों शामिल होना चाहेंगे? प्रतियोगिता एक मुख्य प्रेरणा होगी। स्कूल मालिक यह महशूश करते हैं कि आज समस्या अन्य निजी स्कूलों से मिलने वाली कड़ी प्रतियोगिता है। हैदराबाद की झुग्गियों में एक स्कूल की छत पर से सात अन्य निजी स्कूल दिखाई पड़ते हैं, और वे सभी बच्चों के एक ही समूह के लिए परस्पर प्रतियोगिता करते हैं। स्कूल मालिक अपने को सबसे अलग दिखाने के लिए व्यग्र हैं और अभिभावकों की एक मुख्य चिंता है – शिक्षा की गुणवत्ता। एक ब्रांड नाम में शामिल होकर मैनेजर यह आसानी से सिद्ध कर सकता है कि वह अपने प्रतियोगियों की तुलना में अपने यहाँ गुणवत्ता पर अधिक जोर देता है, और इस प्रकार वह अधिक बच्चों को अपने स्कूल में खींचने में कामयाब हो जाएगा।

अभिभावक अपने बच्चों का दाखिला किसी ब्रांड नेम स्कूल में ही कराना पसंद करेंगे, क्योंकि यह उनकी सूचना–समस्या का एक कारगर समाधान है। बच्चे भी अपने स्कूल के बेहतर पाठ्यक्रम, अध्यापन विधि, तकनीक एवं शिक्षकों के प्रशिक्षण से लाभान्वित होने के कारण ब्रांड नेम स्कूल को ही पसंद करेंगे। वे एक अपेक्षाकृत बड़े संगठन का हिस्सा होंगे, तथा इसके फलस्वरूप मिलने वाले बेहतर नेटवर्क एवं अवसरों से लाभान्वित होंगे। साथ ही ब्रांडनेम की प्रसिद्धि बढ़ने से बच्चों को भी भविष्य में इसका अतिरिक्त लाभ मिलेगा, क्योंकि भविष्य के नियोक्ता अथवा उच्चतर शिक्षण संस्थान उन प्रसिद्ध स्कूलों में पढ़ने के कारण बच्चों पर अधिक विश्वास करेंगे।

उन स्कूलों का क्या होगा, जो स्कूलों के चेन में शामिल नहीं होंगे? तात्कालिक रूप से वे पिछड़ सकते हैं, शायद स्कूल बंद भी करना पड़े – लेकिन इसका कारण सिर्फ एक होगा और वह यह कि अभिभावक अपने बच्चों को वहाँ भेज देंगे, जहाँ उनके खयाल में पढ़ाई बेहतर होती है। लेकिन शिक्षा के गतिशील बाजार में दो बातें होंगी : पहली बात, अलग स्कूल चलाने वाले शिक्षा उद्यमी बच्चों को अपने स्कूल में बरकरार रखने अथवा छोड़ कर चले गये बच्चों को वापस खींचने के लिए अपने यहाँ दी जाने वाली शिक्षा में सुधार लाने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात, और सौ बातों की एक बात, अगर एक शैक्षणिक ब्रांड नेम की वित्तीय एवं शैक्षणिक व्यावहारिकता दिखलाई पड़ती है, तो दूसरे लोग तुरंत उनकी प्रतियोगिता में एक नये ब्रांडनेम के साथ इस बाजार में प्रवेश करेंगे और उतनी ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कम कीमत में पेश कर देंगे।

प्रह्लाद यह पाते हैं कि भारत में विशाल संख्या में गरीबों को कैटेरेक्ट सर्जरी उपलब्ध कराने वाली अरविंद आई केयर सिस्टम के संस्थापक की ''प्रेरणा का स्रोत था मैकडॉनल्ड की हैंबर्गर शृंखला, जहाँ दुनिया भर में हैंबर्गर एवं फ्रैंच फ्राइ की एक समान गुणवत्ता एक गहरी समझ–बूझ तथा मानकीकृत रासायनिक प्रक्रिया का परिणाम है'' (2005, पृ॰ 37)। यहाँ यह सोचने का पर्याप्त कारण है कि उसी प्रकार की ''गहरी समझ एवं मानकीकृत'' अध्ययन प्रक्रिया निजी विद्यालय व्यवस्था के उसी समान सफल मॉडल का भी हिस्सा हो सकती है, जो विशाल संख्या में गरीबों को पढ़ा रही हो।

इस समस्या का समाधान है

विकासशील दुनिया में हर जगह गरीबों के लिए निजी विद्यालय बड़ी तेजी से उभरते जा रहे हैं। वे शहरी एवं सीमांत शहरी क्षेत्रों में गरीब स्कूली बच्चों की अधिकांश आबादी को पढ़ा रहे हैं। उनकी गुणवत्ता उन सरकारी स्कूलों से बेहतर है, जो गरीबों के लिए चलाए जा रहे है। इसमें शायद कोई आश्चर्य भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे मुख्यतः एक व्यवसाय के रूप में, अथात् शुल्क से होने वाली आय के आधार पर, चल रहे हैं, इसलिए अभिभावकों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील हैं। वैसे लोग, जो इस्टरली की तरह इस बात के लिए चिंतित हैं कि किस प्रकार शिक्षा तक गरीबों की पहुँच सुनिश्चित की जाए, वे इस लक्ष्य को हासिल करने में निजी शिक्षा क्षेत्र को काफी उपयोगी पा सकते हैं। गरीबों के निजी स्कूलों में अत्यधिक गरीबों के लिए निःशुल्क अथवा कम शुल्क के आधार पर दाखिला की मानवीय व्यवस्था पहले से ही जारी है। उसी मानवीय व्यवस्था को अगर मानवीय संवेदना के साथ लागू किये जाने वाले लक्षित वाउचर के माध्यम से और आगे बढ़ाया जाए, तो बड़े पैमाने पर शिक्षा तक गरीबों की पहुँच सुनिश्चित की जा सकती है।

सबसे महत्त्वपूर्ण, चूँकि गरीबों को पढ़ाने वाला निजी विद्यालय एक व्यवसाय होता है, और समुचित मुनाफा भी कमा रहा होता है, अतः वह निवेशकों को भी आगे बढ़ने के लिए एक सर्वथा नयी राह दिखाता है। इसका एक तरीका हो सकता है माइक्रोफाइनैंस के जैसी ऋण योजनाओं में निवेश, जिससे कि निजी विद्यालय अपने आधारभूत संरचना में सुधार कर सकें। दूसरा तरीका हो सकता है पाठ्यक्रम एवं शिक्षण शैली में नया प्रयोग करने के लिए निवेश उपलब्ध कराना, जो अगर सफल होता है, तो उसका व्यावसायिक दोहन किया जा सकता है। तीसरा तरीका हो सकता है स्कूलों की शृंखला में निवेश, या तो समर्पित शिक्षा निवेश फंड के माध्यम से अथवा शिक्षा उद्यमियों के साथ साझा उद्यम के माध्यम से, जो गरीब अभिभावकों को सूचना की समस्या से पार पाने में तथा उनके समक्ष शिक्षा के उपलब्ध अवसरों में सुधार करने में मदद कर सकता है।

अमारेच को पढ़ाना एक समस्या तो है, पर उसका समाधान भी है। गरीबों के लिए निजी विद्यालय लेकर आने वाले ''खोजी'' निवेश के लिए लालायित हैं–और सबको बेहतर शिक्षा सुलभ कराने की उनकी केंद्रीय भूमिका में निवेशक उनकी भरपूर मदद कर सकते हैं।

लेखक के बारे में

जेम्स टूली ई.जी. वेस्ट सेंटर के निदेशक हैं। वे यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकैसल में स्कूल ऑफ कम्यूनिकेशन एंड लैंग्वेज साइंसेज के संयुक्त निदेशक तथा शिक्षा प्रभाग (एडूकेशन सेक्शन) के प्रधान हैं। उनका कार्य गरीबों की शिक्षा जरूरतों को पूरा करने में निजी क्षेत्र की भूमिका की पड़ताल करना रहा है।

तालिका 1 कुछ चुने हुए स्थानों पर 'विद्यालयों के विभिन्न प्रकार' एवं 'विभिन्न प्रकार के विद्यालयों में विद्यार्थियों के दाखिले की स्थिति'

	गा, घाना			लागोस राज्य, नाइजीरिया			हैदराबाद, भारत			महबूबनगर, भारत		
विद्यालयों के प्रकार	विद्यालय	विद्यालयों की हिस्सेदारी (प्रतिशत)	विद्यार्थियों की हिस्सेदारी (प्रतिशत)	विद्यालय	विद्यालयों की हिस्सेदारी (प्रतिशत)	विद्यार्थियों की हिस्सेदारी (प्रतिशत)	विद्यालय	विद्यालयों की हिस्सेदारी (प्रतिशत)	विद्यार्थियों की हिस्सेदारी (प्रतिशत)	विद्यालय	विद्यालयों की हिस्सेदारी (प्रतिशत)	विद्यार्थियों की हिस्सेदारी (प्रतिशत)
सरकारी	197	25.3	35.6	185	34.3	26.0	320	34.9	24.0	384	62.4	47.8
निजी तथा सहायताप्राप्त	0	0	0	0	0	0	49	5.3	11.4	13	2.1	4.3
निजी तथा गैर सहायताप्राप्त, गैर मान्यताप्राप्त अथवा गैरपंजीकृत	177	22.7	15.3	233	43.1	33.0	335	36.5	23.1	77	12.5	6.6
निजी तथा गैर सहायताप्राप्त, मान्यताप्राप्त अथवा पंजीकृत	405	52.0	49.1	122	22.6	42.0	214	23.3	41.5	141	22.9	41.2
कुल	779	100	100	540	100	100	918	100	100	615	100	100

स्रोत : टूली एवं डिक्सन 2006बी में विद्यालयों का सर्वे (2004–5)

तलिका 2 मकोको, लागोस राज्य, नाइजीरिया में 'गरीबों के लिए चलने वाले एक साधारण निजी विद्यालय' का आय एवं व्यय

मद	रकम नाइरा में	रकम यू. एस. डॉलर में
टर्म शुल्क	1,800	12.41
प्रति माह शिक्षकों का वेतन	4,388	30.26
रीकरेंट मासिक खर्च	7,450	51.38
स्कूल मालिक का मासिक वेतन	8,000	55.17
वार्षिक आय	10,81,080	7,455.72
वार्षिक खर्च	8,69,928	5,999.50
वार्षिक मुनाफा	2,11,152	1,456.22
आय के प्रतिशत में वार्षिक मुनाफा	20	20

टिप्पणी : माना गया है कि विद्यालय में 220 विद्यार्थी एवं 13 शिक्षक हैं।
स्रोत : लेखक का आँकलन

CENTRE FOR CIVIL SOCIETY
K-36 Hauz Khas Enclave, New Delhi 110 016
Voice: 2653 7456/ 2652 1882 Fax: 2651 2347
Email: ccs@ccs.in Website: www.schoolchoice.in